जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 12 संख्याः 261 प्रभात चूरू, गुरुवार 14 जनवरी, 2021 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

दिल्ली सीमा पर आंदोलनरत किसानों ने बुधवार को लोहड़ी मनाई और लोहड़ी के अलाव में विवादास्पद कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं। फसल कटाई के इस पर्व की उत्तर भारत में भारी धूम होती है, खासकर पंजाब, हरियाणा, जम्मु -कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली में। किसानों ने अपने घर-परिवार से दूर लोहड़ी पर्व मनाया और कहा कि यह सब वे अपने परिवार के भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ज़िद पर अड़ी रही तो वे आगामी फसल नहीं बोने का निर्णय भी कर सकते हैं।

आने वाले दिनों में क्या होगा, इसका खाका तैयार करके लौटे वेणुगोपाल

कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की यात्रा क्या राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में आने वाले बदलाव का संकेत है?

- **गहलोत, पायलट और डोटासरा से चर्चाओं का मतलब यही हो सकता है, कि सहमति के आधार पर मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं।**
- **हालांकि खुद वेणुगोपाल ने अपनी यात्रा का उद्देश्य संसद के आगामी सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करना बताया है।**

जयपुर, 13 जनवरी (का.प्र.)। राजस्थान कांग्रेस में बुधवार का दिन चर्चाओं से अटा रहा। इसका कारण यह था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मंगलवार की रात अचानक जयपुर आए और उनका जयपुर आना एक ऐसी घटना रही जिसका किसी को अधिक अंदेशा नहीं था। उनके आने के बाद बुधवार को उनकी सिर्फ तीन नेताओं से मुलाकात हुई। इन नेताओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ,पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। वेणुगोपाल ने इनके अलावा किसी अन्य नेता से मुलाकात नहीं की। यानी कि कहने को भले ही उन्होंने मीडिया से यह कहा कि "वे चूंकि राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं तथा आगामी संसद सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जयपुर आए हैं, लेकिन कोई भी सांसद सिर्फ इसलिए अचानक राज्य की यात्रा करें कि उसे संसद में उठाने वाले मुद्दों पर चर्चा करनी है तो राजनीतिक हलकों में भी कोई यह बात मानने को तैयार नहीं होगा।

दरअसल राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में उतार-चढ़ाव तो कई बार देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार जिस तरह की स्थितियां पिछले 1 साल से बनी हुई है वह पार्टी स्तर पर बहुत आसान नहीं कही जा सकती है, क्योंकि पहली बार तीसरी बार के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत को सचिन पायलट के रूप में मजबूत प्रतिद्वंदी मिला है। यह प्रतिद्वंदिता कोई निजी नहीं बल्कि राजनीतिक है और इसी प्रतिद्वंदिता का नतीजा है कि राजस्थान की राजनीति में इस तरह की स्थितियां पहली बार बनी, कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के दो धड़े अलग-अलग जगह पर विधायकों के साथ बाड़ाबंदी कर रहे थे। इसी बाड़ेबंदी का नतीजा था कि कांग्रेस आलाकमान को मामले को हल करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करनी पड़ी, जिसके एक सदस्य स्वयं के.सी. वेणुगोपाल हैं और दूसरे सदस्य अजय माकन हैं, जो कि अब राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव है और कमेटी के तीसरे सदस्य अहमद पटेल दिवंगत हो चुके हैं। अब राजस्थान की कांग्रेस में सत्ता और संगठन को लेकर जो भी फैसले होने हैं, उनमें प्रमुख भूमिका केसी वेणुगोपाल और अजय माकन की रहनी है। ऐसे में केसी वेणुगोपाल की अचानक हुई राजस्थान यात्रा को लेकर कई तरह की चर्चाएं होना स्वाभाविक है।

अब जिस तरह से राजनीतिक स्थितियां राजस्थान में बनी हुई है, उसके अनुरूप केसी वेणुगोपाल की राजस्थान की यह यात्रा और यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ लंबी वार्ता यह संकेत जरूर देती है कि आने वाले डेढ़ 2 महीनों के दौरान राजस्थान में सत्ता और संगठन में जो कुछ भी होना है, उसका खाका तैयार हो चुका है और उसी पर चर्चा के लिए शायद वेणुगोपाल राजस्थान आए थे। यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पोल्ट्री प्रतिबंध

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जनवरी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने बुधवार को कहा कि बर्ड फ्लू जम्मू-कश्मीर के गंदरबल जिले तथा झारखंड के चार जिलों तक पहुंच गया है तथा इसके अलावा, 10 राज्यों में इसके फैलने की पुष्टि सोमवार को ही हो गई थी।

- **केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगाएं।**

विभाग ने राज्यों को यह भी सलाह दी कि वे अन्य राज्यों से आने वाले मुर्गों (कुक्कुट) तथा अण्डे की सप्लाई पर रोक नहीं लगायें तथा अगर रोक लगा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विवादित कृषि कानून जलाकर आंदोलनकारी किसानों ने लोहड़ी मनाई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **त्यौहार पर परिवार से दूर रहने की उदासी तो थी पर किसानों ने कहा कि वे यह सब परिवार के भविष्य के लिये कर रहे हैं।**
- **ज्ञातव्य है कि उत्तर भारत में लोहड़ी फसल कटाई का पर्व है। किसानों ने यह भी कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो वे अगली फसल की बुवाई नहीं करेंगे।**

नई दिल्ली, 13 जनवरी। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों ने बुधवार को तीन विवादित कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मनाई त्यौहार उत्तर भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं जम्मू-कश्मीर में बहुत उल्लास से मनाया जाता है। परन्तु फसल कटाई के मौसम की शुरूआत का यह त्यौहार इस बार इन किसानों ने उदासपूर्ण माहौल में बगैर परिवार के मनाया।

जो किसान पंजाब से आए थे वे अपने साथ नई फसल की सिकी भुनी हुई मकई ले कर आए थे जिसे उन्होंने किसानों में वितरित किया जबकि किसानों ने ठंड के दिनों को अलविदा कहने के लिए विभिन्न आंदोलन स्थलों पर अलाव जलाया तथा उन्होंने उन लोगों के बीच खीर, गुड व जनवरी के गन्ने की फसल से बनी गजक व मूंगफली खाकर लोहड़ी का त्यौहार मनाया।

लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है जो कि फसलों का त्यौहार है जिसे सम्पूर्ण भारत भिन्न-भिन्न नामों से मनाया जाता है मकर संक्रांति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल में इसी नाम से मनाया जाता है तमिलनाडू में पोंगल एवं असम में बिहु के नाम से मनाया जाता है।

सिंघु बॉर्डर के किसानों ने कहा कि इस बार वे परिवार के साथ इस उत्सव को नहीं बना पाए परन्तु वे दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे क्योंकि उनका यह कार्य परिवार के भविष्य के लिए किया जा रहा है। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि यदि सरकार अपनी बात पर अड़ी रहती है तो वे आगामी जून में नई फसल नहीं बोने का खतरनाक निर्णय भी कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कृषि कानूनों की प्रतियां सरकार के अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए जलाई हैं और उसके बाद संयुक्त रूप से प्रार्थना की गई कि किसानों को उनके अधिकार वापस मिले। उन्होंने कहा कि उनके किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत गठित की गई समिति का स्पष्ट रूप से विरोध किया है क्योंकि वे इस बात पर अडिग हैं कि वे कृषि कानूनों के निरस्तीकरण से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे।

किसान एकता मोर्चा ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। जिसकी रूपरेखा का ऐलान शुक्रवार को होने वाली पूर्व निर्धारित किसान सरकार की वार्ता के एक दिन बाद किया जाएगा।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहु, उत्तरायण व पौष पर्व के अवसर पर देश की जनता को बधाई व शुभकामनाएं दी है। एक ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति कोविंद ने कामना की है कि ये त्यौहार हमारे समाज में प्रेम, स्नेह और एकता के बंधन को मजबूत बनाएंगे और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सेना में व्यभिचार

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 13 जनवरी। केन्द्र बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ओर कहा कि उसके 2018 निर्णय जिसमें व्याभिचार को अपराध नहीं मानार गया है इसे सशस्त्र सेनाओं में लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें इस कृत्य को 'अनुचित आचरण' का कृत्य माना गया है ओर इस आधार पर कोर्ट मार्शल किया जाता है।

- **केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि सन् 2018 में व्यभिचार को गैर अपराध करार दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सेना को अलग रखा जाए।**

केन्द्र ने अपनी याचिका में कहा है कि सशस्त्र सेना के सैनिकों के द्वारा अपने साथी कर्मी की पत्नी के साथ व्याभिचार करने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि यह "अनुचित आचरण" है और सशस्त्र बलों में अनुशासन के लिए इसे रखा जाना चाहिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रदेश भाजपा में डॉ. सतीश पूनिया को मिला फ्री हैंड

- **लेकिन वसुंधरा खेमे ने नाराजगी जताई कि पूनिया के नेतृत्व में भाजपा को निकाय चुनाव में सफलता नहीं मिली है**
- **वसुंधरा खेमे ने इस संबंध में केन्द्रीय नेतृत्व से शिकायत की।**
- **लेकिन भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने 28 जनवरी को होने वाले 90 नगर निकाय चुनावों की पूरी जिम्मेवारी डॉ. पूनिया को सौंपी।**

जयपुर, 13 जनवरी (का.सं.)। राज्य में पिछले दिनों सम्पन्न हुए 50 नगर निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशानुकूल सफलता नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए वसुंधरा राजे खेमे से माने जाने वाले कई नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रदेश नेतृत्व की शिकायत की है।

वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव में भाजपा को मिली सफलता को देखते हुए इस माह की 28 तारीख को होने वाले 90 नगर निकाय चुनाव, उसके बाद तीन जगह पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों के साथ ही 12 जिलों में होने वाले पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव प्रबंधन के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया को फ्री हैण्ड दे दिया है।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि भाजपा के वर्तमान प्रदेश नेतृत्व की शिकायत करने वाले नेताओं में जयपुर के दो मौजूदा विधायक, एक पूर्व विधायक और दो राज्यसभा सांसद शामिल हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा निकाय चुनाव में टिकट बंटवारा सही नहीं किए जाने और कद्दावर नेताओं को मैदान में नहीं उतारे जाने की शिकायत की गई हैं। भाजपा के दिल्ली सूत्रों का दावा है कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, विधायक कालीचरण सराफ, अशोक लाहोटी, पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने केंद्रीय नेतृत्व से राज्य नेतृत्व, खासतौर से अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए टिकट बंटवारे समेत कई तरह की शिकायतें की हैं। इन सभी नेताओं को वसुंधरा राजे खेमे से माना जाता है। शिकायत करने वालों की लिस्ट में कुछ भाजपा कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का नाम भी ले रहे हैं, जिनका बेटा भाजपा टिकट मिलने के बावजूद पिछले दिनों चुनाव हार गया था।

इधर, जानकारी में आया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दिल्ली पहुंच गई हैं, वह अगले कुछ दिन दिल्ली में ही रहने वाली हैं। इस दौरान उनका जेपी नड्डा से मिलने का भी कार्यक्रम है। उल्लेखनीय है कि तीन दिन पहले ही भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सतीश पूनियां, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर दिल्ली गए थे। बताया जाता है कि भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने इन चारों नेताओं से वसुंधरा खेमे के नेताओं द्वारा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

करोना वैक्सीन की 5.50 लाख डोज़ प्रदेश पहुंचीं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 13 जनवरी। प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सिन और कोविशील्ड वैक्सीन बुधवार को एयर

- **हैदराबाद से सुबह 11 बजे भारत बायोटैक कंपनी की कोवैक्सीन और शाम को पुणे से सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। इसके अलावा उदयपुर में भी एक लाख के लगभग डोज़ पहुँची हैं।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जहरीली शराब

रूपबास, भरतपुर, 13 जनवरी (निसं)। भरतपुर जिले में रुपबास थाना क्षेत्र के उत्तर प्रदेश से सटे चक सामरी गांव में बीतीरात जहरीली शराब पीने से सरपंच के भाई सहित 4 जनों की मौत हो गई। शराब सेवन के बाद तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराए गए कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने की भी खबरें हैं।

- **रूपवास के गांव चकसामरी में जहरीली शराब पीने से 4 ग्रामीणों की मौत हुई, पुलिस मामले की जाँच में जुटी।**

मृतकों में प्रीतम सिंह पुत्र धर्म सिंह, मांगीलाल पुत्र चन्दन सिंह कम्पोटर व रणजीत शामिल है। इनमें प्रीतम नोहरदा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'केन्द्र सरकार ने कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दिया'

कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में दायर केन्द्र सरकार के शपथ पत्र को भ्रामक और झूठा करार दिया

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- **सिंघवी ने कहा कि केन्द्र सरकार का यह दावा गलत है कि कृषि कानून बनाने से पहले वृहद स्तर पर चर्चा की गई थी।**
- **सिंघवी ने कहा कि सन् 2020 में बनाए गए कानून के लिए 2003 और 2017 के मॉडल एक्ट का हवाला दिया गया है, जो बताता है कि इन कृषि कानूनों के निर्माण से पूर्व कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था।**

नई दिल्ली, 13 जनवरी। कांग्रेस ने बुधवार को मोदी सरकार पर जबरदस्त प्रहार करते हुये कहा कि उसने अपने सोमवार के हलफनामे में सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया था। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि इन तीनों कृषि कानूनों को लाने से पहले, पर्याप्त मंत्रणा की गई थी।

पार्टी प्रवक्ता तथा वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ऑनलाइन प्रैस कॉन्फ्रेंस को बताया कि यह अदालत एवं राष्ट्र को "बहकाने, छल-कपट करने, मिथ्या एवं अयथार्थ सूचना देने" का प्रयास था।

सरकार ने अपने शपथ पत्र में कहा था कि यह शपथ पत्र "आंदोलनकारियों द्वारा फैलाये गये इस भ्रामक विचार का पर्दाफाश करने के प्रयोजन से पेश किया जा रहा है कि केन्द्र सरकार एवं संसद ने संदर्भित कानूनों को पारित करने से पहले, न तो कोई परामर्श-प्रक्रिया अपनाई थी और किसी कमेटी द्वारा इन मुद्दों का परीक्षण ही कराया था।"

सरकार ने विधायिका में विचार-विमर्श होने से पहले के उदाहरण देते हुये कहा कि कानून बनाये जाने से पहले, वर्ष 2000 में 'गुरु कमेटी' गठित की गई थी तथा अन्य प्रक्रियाओं के अलावा, सरकार ने 2003 तथा 2017 में ड्राफ्ट मॉडल एक्ट राज्य सरकारों के पास भेजे गये थे। सरकार ने दावा किया था कि "ये कानून जल्दबाजी में नहीं बनाये गये, बल्कि दो दशकों के विचार-विमर्श का परिणाम है।"

सिंघवी ने कहा कि यह शपथ पत्र सरकार की इस खामी की कलई खोलता है कि औपचारिक विचार-विमर्श तक नहीं किये गये। उन्होंने कहा, "क्या इसे विस्तृत परामर्श प्रक्रिया कहा जा सकता है? जिस कानून को आप 2020 में ला रहे हैं, उसके लिये आप 2003 तथा 2017 के मॉडल अधिनियमों को प्राथमिकता दे रहे हैं।" उन्होंने जोर देते हुये कहा कि यह इस बात का खुला एवं स्पष्टीकरण है कि पिछले साल जून में संबंधित अध्यादेश जारी करने तथा सितम्बर में संसद में विधेयक पेश करने से पहले 2019 या 2020 में किसी प्रकार का कोई विचार-विमर्श या परामर्श नहीं किया गया।

सिंघवी ने कहा कि ये कानून संसद के गले बांध दिए गए। उन्होंने कहा, "सरकार सदैव ही झूठ बोलकर भारत की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करती आई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस बार सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं बख्शा।"

सिंघवी ने कहा कि मॉडल अधिनियम राज्यों के पास पालनार्थ भेजे गये थे क्योंकि सरकार अखिल भारतीय अधिनियम पारित करने की विधायी क्षमता के घोर अभाव से अच्छी तरह परिचित थी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, "मॉडल अधिनियमों की विषय वस्तु भी उन तीनों कानूनों से अलग थी, जिन्हें चर्चा के बिना पारित कर दिया गया। मॉडल कानूनों का राज्यों के पास भेजा जाना भी यह दर्शाता है कि केन्द्र सरकार इन कानूनों को पारित कराने में अपनी क्षमता से परे चली गई थी।"

एलन के 3 छात्र ऑक्सफोर्ड में

कोटा, 13 जनवरी (निसं)। देश में जेईई और नीट के रिजल्ट्स में इतिहास रचने के बाद अब एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट अंतरराष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के आयाम स्थापित कर रहा है। दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में एलन ग्लोबल स्टडीज डिविजन (एजीएसडी) के 3 स्टूडेंट्स को सफलता मिली है। एलन के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने बताया कि संस्था के छात्र तेजस मित्तल, ओजस मित्तल और अश्वत जैन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी

- **दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से एक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यू.के. में एलन ग्लोबल स्टडीज़ डिविज़न के तीन छात्र तेजस मित्तल, ओजस मित्तल और अश्वत जैन का चयन हुआ है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)